

प्रेषक,

राधा रतूडी,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

समस्त जिलाधिकारी,  
उत्तराखण्ड।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अनुभाग-2

देहरादून दिनांक 30 दिसम्बर, 2014

विषय: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित आबादी के अतिरिक्त राज्य की शेष 39,22,800 आबादी को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए उत्तराखण्ड राज्य खाद्य योजना के लाभार्थियों का चयन एवं राशन कार्ड वितरण करने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं०- 801/14-XIX-2/89 खाद्य/2013 दिनांक 04.03.2014 द्वारा उत्तराखण्ड राज्य की 1,01,16,800 आबादी में से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अधीन भारत सरकार द्वारा निर्धारित 61.94 लाख आबादी के अतिरिक्त जो परिवार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से लाभान्वित होने से वंचित रह गये हों, ऐसी अवशेष 39,22,800 आबादी को खाद्यान्न मुहैया कराने के उद्देश्य से "उत्तराखण्ड राज्य खाद्य योजना" का प्रारम्भ एवं इस योजना के लाभार्थियों को प्रतिमाह प्रति राशनकार्ड 10 कि०ग्रा० गेहूँ तथा 05 कि०ग्रा० चावल उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

इसी क्रम में अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा दिनांक 01.04.2015 से प्रत्येक दशा में राशन कार्ड डिजिटাইजेशन का कार्य पूरा करते हुये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना को राज्य में लागू करने के निर्देश दिये गये हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत राज्य की 61.94 लाख जनसंख्या को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना तथा अन्त्योदय अन्न योजना के राशन कार्ड जारी किये जा चुके हैं। राज्य सरकार द्वारा राज्य की अवशेष 39,22,800 आबादी को राज्य खाद्य योजना के अन्तर्गत आच्छादित कर खाद्यान्न उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है। ऐसे परिवारों के चयन हेतु निम्न प्रक्रिया अपनायी जायेगी:-

- 1- राज्य खाद्य योजना के अन्तर्गत प्रत्येक ऐसे परिवारों को जिनकी वार्षिक आय ₹ 5.00 लाख या उससे अधिक हो तथा आयकर दाता के रूप में **Second Slab (20%)** के आयकर दाता हों, को छोड़ते हुये शेष आबादी के सभी परिवारों को उत्तराखण्ड राज्य खाद्य योजना में चयनित किया जाना है।
- 2- राशन कार्ड जारी करने हेतु पात्र परिवारों के चयन की प्रक्रिया के सम्बन्ध में शासनादेश सं०- 361/13-XIX-2/40 खाद्य/2009 दिनांक 15.07.2013 तथा शासनादेश सं०- 427/13-XIX-2/40 खाद्य/2009 दिनांक 07.08.2013 के अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। यह भी उल्लेखनीय है कि ऐसे परिवार जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की पात्रता रखते हैं किन्तु वे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित किये जाने से वंचित रह गये हों, ऐसे परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर राज्य खाद्य योजना में सम्मिलित किया जाय।

क्रमशः...2 पर

- 3- राशनकार्डों के नवीनीकरण तथा निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में शासन के आदेश संख्या-436/09-XIX/खाद्य/111 एम/2009 दिनांक 25.02.2009 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
- 4- राज्य खाद्य योजना के अन्तर्गत नवीन राशन कार्ड महिला मुखिया के नाम बनाये जायेंगे। महिला मुखिया न होने की स्थिति में परिवार के वरिष्ठतम पुरुष मुखिया के नाम राशन कार्ड बनाये जायेंगे।
- 5- राज्य खाद्य योजना के अन्तर्गत एक जांच पत्र भरवाया जायेगा। भविष्य में राज्य खाद्य योजना के जांच पत्रों का भी डिजीटाइजेशन किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु शहरी क्षेत्र के जांच पत्र जिला पूर्ति कार्यालय में तथा ग्रामीण क्षेत्र के जांच पत्र खण्ड विकास कार्यालय में सुरक्षित रूप से अनुरक्षित रखवाये जायें।
- 6- जांच पत्र हेतु वोटर आईडी, बैंक पासबुक की छायाप्रति अथवा आधार कार्ड में से कोई एक अभिलेख अनिवार्य रूप से लिया जायेगा।
- 7- राज्य खाद्य योजना से सम्बन्धित राशन कार्ड एवं जांच पत्र में जीत प्रिन्टर्स द्वारा जनपदों को उपलब्ध करा दिये गये हैं। यदि किसी जनपद को पूर्व में सूचित संख्या से कम राशन कार्ड या जांच पत्र प्राप्त हुए हो तो तत्काल आयुक्त कार्यालय को अवगत कराया जाय।

उक्त के क्रम में पुनः अपेक्षित है कि राज्य खाद्य योजना को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के साथ दिनांक 01 अप्रैल, 2015 से लागू किये जाने हेतु प्राथमिकता के आधार पर उपरोक्तानुसार कार्यवाही करते हुये राज्य खाद्य योजना के लाभार्थियों का चयन व राशन कार्डों का वितरण सुनिश्चित किया जाय।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी),  
प्रमुख सचिव

सं० 382/14-XIX-2/89 खाद्य/2013 तददिनांकित

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- सचिव, ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- सचिव, शहरी विकास एवं गरीब उन्मूलन, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ सम्भाग, पौड़ी/नैनीताल।
- 4- आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 5- समस्त जिलापूर्ति अधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 6- समन्वयक, एनओआईसी, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
- 6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रकाश चन्द्र भट्ट),  
उप सचिव